Mukhyamantri Kanyadan Yojana (Rajasthan)

The Mukhyamantri Kanyadan Yojana of Rajasthan is being carried out by the Social Justice and Empowerment Department to encourage the marriages of the girls belonging to poorer families directly by providing financial aid. The scheme is also being brought into focus as a transparent good governance initiative under the leadership of Chief Minister Bhajan Lal Sharma through end-to-end online processes. Since FY 2023-24 to date, the department has incurred an approximate expenditure of 142.62 crore and helped 34,704 girls. The scheme also associates the support to education in that extra amount of incentives is given according to the education level of the girl to motivate the schooling and further education.

KEY FEATURES

- The Social Justice and Empowerment Department implemented it.
- Provision of financial aid on marriage to the eligible families.
- Extra incentive rate based on the education level of the girl.
- Aid is sent via DBT to the bank of the beneficiary.
- Online application through fully online application on the portal of SJMS (self-apply or e-Mitra).
- Interconnected with Jan-Aadhaar portal to prevent unnecessary and increased paperwork.

Education related incentives and financial support.

• 31,000 marriage allowance given to BPL families in:

- Scheduled Castes (SC)
- Scheduled Tribes (ST)
- Minority communities

• marriage aid of 21,000 is given to:

- Other BPL families
- Antyodaya families
- Astha cardholders
- Special-abled persons (persons with disabilities).
- Girls were being advantaged by the Palanhar scheme.
- Women sportspersons

Education based incentive amount:

- -In case the girl is Class 10 pass: 10,000 additional.
- In case the girl is a graduate: Additional 20000.

Eligibility and Process of Application.

• The girl should be of age (must be above 18 years).

- The benefit can be given to only a maximum of two daughters per family.

Application may be made:

- Online by use of SSO ID in the Social Justice Management System (SJMS) portal, or
- Through e-Mitra

The amount of assistance is deposited through DBT directly to the bank account of the beneficiary.

- The timeframe of the application was extended to 1 year.
- Previously, the limit of time of application was up to 6 months of the marital date.
- The present day government has increased limit to 1 year after marriage in order that the qualified families are not left out because of the tough situations.

JAN-AADHAAR combination and computer-aided authorization.

- The scheme has been incorporated with Jan-Aadhaar portal to enhance transparency and ease approvals.

RASonly

The details obtained using Jan-Aadhaar include:

- Domicile status
- Caste certificate
- BPL status
- Antyodaya/Astha card
- Income certificate
- Certificate of registration of marriage.
- Bank account details

On submission the online verified data is automatically fetched to the scheme portal reducing the paperwork and minimizing human intervention on the scheme portal.

BACKGROUND AND EVOLUTION

- 1997-98: Initially marriage grant assistance started to daughters of widows.
- 2005: Elaborated to SC/ST BPL families.
- 2016-17: renamed to Sahyog evam Uphaar Yojana.
- It is now under the Mukhyamantri Kanyadan Yojana with wider timelines and Jan-Aadhaar-based digital integration.

CONCLUSION

Mukhyamantri Kanyadan Yojana has emerged as a significant social support program in Rajasthan in alleviating the financial cost of marrying a poor and vulnerable family and promoting the education of girls by providing them with other incentives. By incurring ₹142.62 crore expenses and benefiting 34,704 beneficiaries since 202324, the scheme shows the implementation of DBT-based delivery and integration of Jan-Aadhaar as viable measures towards transparent and citizen-friendly governance.

MCQs (RAS PRELIMS PATTERN)

1. In the Mukhyamantri Kanyadan Yojana, which type gets 31000 marriage assistance?

   (a) All Antyodaya families

   (b) minority BPL families, SC/ST.

   (c) BPL families (universally).

   (d) Only women sportspersons

   Answer: (b)

RASonly

The scheme gives a 31,000 amount to BPL families of SC, ST, and minorities, whereas other eligible groups get 21,000 amount.

2. What is the existing maximum period of time within which one can apply to receive assistance after marriage within the scheme?

(a) 3 months

(b) 6 months

(c) 9 months

(d) 1 year

Answer: (d)

The period of application has been increased by 1 year instead of the 6 months period to allow deserving families not to go unrewarded by unfavorable events.

3. What do you think is the best statement to be made about the role of Jan-Aadhaar integration in the scheme?

(a) It eliminates the DBT transfers.

(b) It restricts verification to offices only offline.

(c) It automatically retrieves authenticated documents/data to minimize paperwork.

(d) It restricts the scheme to urban beneficiaries only.

Answer: (c)

The Jan-Aadhaar integration allows automated retrieval of verified information, including domicile, caste, BPL status, income, marriage registration, and bank details, which will save a lot of paperwork and reduce human intervention.

RASonly

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (राजस्थान)

राजस्थान की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस योजना को पारदर्शी "सुशासन" पहल के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। वित्तीय वर्ष 2023–24 से अब तक विभाग द्वारा लगभग ₹142.62 करोड़ व्यय किए गए हैं और 34,704 कन्याओं को लाभ मिला है। यह योजना शिक्षा से भी जुड़ी है, क्योंकि कन्या की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे पढ़ाई और उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिले।

मुख्य विशेषताएँ

• योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।
• पात्र परिवारों को विवाह के समय वित्तीय सहायता दी जाती है।
• कन्या की शिक्षा के स्तर के अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।
• सहायता राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
• आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और SJMS पोर्टल पर SSO ID से स्वयं या e-Mitra के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
• जन-आधार पोर्टल से एकीकरण कर कागजी कार्यवाही कम की गई है और प्रक्रिया सरल बनाई गई है।

शिक्षा-आधारित प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता

• ₹31,000 की विवाह सहायता BPL परिवारों को दी जाती है, जो निम्न श्रेणियों में आते हैं:
– अनुसूचित जाति (SC)
– अनुसूचित जनजाति (ST)
– अल्पसंख्यक समुदाय

• ₹21,000 की विवाह सहायता निम्न को दी जाती है:
– अन्य BPL परिवार
– अंत्योदय परिवार
– आस्था कार्डधारी
– विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन)
– पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएँ
– महिला खिलाड़ी

शिक्षा के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि

– यदि कन्या कक्षा 10वीं उत्तीर्ण है: अतिरिक्त ₹10,000
– यदि कन्या स्नातक है: अतिरिक्त ₹20,000

पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया

• कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• एक परिवार की अधिकतम दो बेटियाँ इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकती हैं।
• आवेदन निम्न प्रकार किया जा सकता है:
– SSO ID के माध्यम से SJMS पोर्टल पर ऑनलाइन, या
– e-Mitra के माध्यम से
• सहायता राशि DBT द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है।

आवेदन की समय-सीमा 1 वर्ष तक बढ़ाई गई

• पहले विवाह तिथि के बाद आवेदन की समय-सीमा 6 महीने तक थी।
• वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर विवाह के बाद 1 वर्ष कर दिया है, ताकि कठिन परिस्थितियों के कारण कोई पात्र परिवार लाभ से वंचित न रह जाए।

RASonly

जन-आधार एकीकरण एवं डिजिटल सत्यापन

• पारदर्शिता बढ़ाने और स्वीकृति प्रक्रिया आसान करने हेतु योजना को जन-आधार पोर्टल से जोड़ा गया है।
• जन-आधार से निम्न विवरण प्राप्त किए जाते हैं:
– मूल निवास स्थिति
– जाति प्रमाण पत्र
– BPL स्थिति
– अंत्योदय/आस्था कार्ड विवरण
– आय प्रमाण पत्र
– विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
– बैंक खाता विवरण
• आवेदन जमा करते ही ऑनलाइन सत्यापित डेटा स्वतः योजना पोर्टल पर फेच हो जाता है, जिससे कागजी कार्यवाही कम होती है और मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होता है।

पृष्ठभूमि एवं विकास

• 1997–98: शुरुआत में विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान सहायता शुरू हुई।
• 2005: इसका विस्तार SC/ST BPL परिवारों तक किया गया।
• 2016–17: इसे "सहयोग एवं उपहार योजना" नाम दिया गया।
• वर्तमान में यह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के रूप में विस्तारित समय-सीमा और जन-आधार आधारित डिजिटल एकीकरण के साथ संचालित है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान में गरीब और कमजोर परिवारों पर विवाह के आर्थिक बोझ को कम करने तथा बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक सहायता योजना के रूप में उभरकर सामने आई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 से अब तक ₹142.62 करोड़ व्यय कर 34,704 कन्याओं को लाभ दिया गया है। DBT के माध्यम से भुगतान और जन-आधार एकीकरण इस योजना को पारदर्शी, सरल और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में प्रभावी कदम हैं।

MCQs (RAS प्रीलिम्स पैटर्न)

1. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ₹31,000 की विवाह सहायता किस श्रेणी को मिलती है?
   (a) सभी अंत्योदय परिवार
   (b) अल्पसंख्यक BPL परिवार तथा SC/ST
   (c) सभी BPL परिवार (सार्वभौमिक रूप से)
   (d) केवल महिला खिलाड़ी
   उत्तर: (b)
   यह योजना SC, ST और अल्पसंख्यक समुदाय के BPL परिवारों को ₹31,000 देती है, जबकि अन्य पात्र श्रेणियों को ₹21,000 की सहायता दी जाती है।

2. योजना के अंतर्गत विवाह के बाद सहायता के लिए आवेदन करने की वर्तमान अधिकतम समय-सीमा क्या है?

RASonly

(a) 3 महीने
(b) 6 महीने
(c) 9 महीने
(d) 1 वर्ष
उत्तर: (d)
आवेदन की समय-सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कोई पात्र परिवार लाभ से वंचित न रह जाए।

3. योजना में जन-आधार एकीकरण की भूमिका के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन-सा है?
(a) यह DBT ट्रांसफर को समाप्त कर देता है।
(b) यह सत्यापन को केवल दफ्तरों में ऑफलाइन तक सीमित करता है।
(c) यह प्रमाणित दस्तावेज/डेटा स्वतः फेच कर कागजी कार्यवाही कम करता है।
(d) यह योजना को केवल शहरी लाभार्थियों तक सीमित करता है।
उत्तर: (c)
जन-आधार एकीकरण से मूल निवास, जाति, BPL स्थिति, आय, विवाह पंजीकरण और बैंक विवरण जैसे सत्यापित डेटा का स्वतः प्राप्त होना संभव होता है, जिससे कागजी कार्यवाही घटती है और मानवीय हस्तक्षेप कम होता है।

Rajasthan AI-ML Policy 2026 and National AI Literacy Program.

Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma introduced Rajasthan AI-ML Policy 2026 and the National AI Literacy Program in the inauguration of the opening session of the Rajasthan Regional AI Impact Conference-2026 at JECC, Jaipur (06 January). Through them, the state also introduced iStart Learning Management

System, Rajasthan AVGC-XR Portal, and the Rajasthan AI Portal. These initiatives will help the government to speed up the pace of AI-based education, startups, research, skilling and digital governance, and support innovation and entrepreneurship in new areas of IT in Rajasthan.

KEY LAUNCH announced in JECC, Jaipur .

- National AI Literacy Program
- Rajasthan AI-ML Policy 2026
- iStart Learning Management System (LMS)
- Rajasthan AVGC-XR Portal
- Rajasthan AI Portal

Live streaming of HOLOGRAPHIC MOU SIGNING.

- Three key MoUs that had been signed at Yojana Bhawan were projected live at JECC through a 98-inch holographic projection screen.
- It was also reported as the first holograph experience in a live government event and the ones before it were displayed on international levels such as G-20.
- The holographic display was created by Kalens, a startup that is registered by iStart and was created by Rajat Jain.
- Google, IIT Delhi and National Law University (NLU) Jodhpur were the participants in the MoUs.

RAJASTHAN AI-ML POLICY 2026: E-Governance-led by AI.

Rajasthan AI-ML Policy 2026 has been proposed in order to transform Rajasthan into an IT/ITeS hub and scale e-governance with the help of AI and ML in Singapore service delivery. The policy is intended to provide the responsible, ethical, and safe use of AI/ML in order to make the government service faster, more transparent, and more centered on people, as well as enhance the efficiency of administration and economic growth based on innovation.

CORE OBJECTIVES

- Make the delivery of essential services to citizens faster, transparent, and citizen-focused by making use of responsible AI/ML.
- Foster innovation-driven economic growth and improve the efficiency of the administration.
- Have ethical, accountable and privacy-conserving AI systems in governance.

Grants of Data security and cyber security.

- The focus on ensuring the transparency, accountability, fairness, and privacy of AI systems.

RASonly

- Policies to minimize possible bias of AI systems and enhance transparency in decision making.
- Unambiguous reporting and resolution of AI-based cyber crimes.
- Proposals to set up Artificial Intelligence Center of Excellence in the state.

Implementation and Capacity building.

• Every department shall like to have AI use-cases in every department and assign an AI Nodal Officer.

• Creation of current digital and compute infrastructure, AI cloud and secure data storage, and testing environment.

• AI education promotion in schools, ITIs, polytechnic institutes, and colleges.

• AI education of young people, educators, and government.

• AI to RIPS, MSME, and Startup incentives in the top-up schemes in industry, MSME, start ups, and research institutions.

NATIONAL Artificial Intelligence Literacy Program: “ AI ALL In A Simple, Practical Form.

- Introduced to turn the mass audience into AI-literate and establish viable technology competencies.
- Not only to train experts and coders but also kids and common youth to understand the basics of AI.
- The initial step is the stage of Yuva AI to All, which includes a 4-hour course.
- The course describes AI in a clear and practical manner and addresses the ways of responsible use in such fields as creativity, planning, and daily life.

MOUS, GOOGLE and NLU JODHPUR.

- Pilot projects in health, agriculture, transport, and citizen services: AI/ML-based pilot projects at Google and support based on cloud and AI implementation using global best practices.
- NLU Jodhpur: Building of responsible, ethical, and trustworthy AI, and government officer, startup, and professional capacity building.
- IIT Delhi: Partnership on an AI Center of Excellence, research, skilling, Hackathons, startup mentoring and intensified industry-academia-government connectivity.

CONCLUSION

The Rajasthan AI-ML Policy 2026 and the National AI Literacy Program are both indicative of an AI inclination to governance, skilling and innovation in Rajasthan. Having ethical safeguards, cyber security emphasis, department level AI implementations and collaborations with Google, IIT Delhi and NLU Jodhpur, the

RASonly

state expects to enhance service delivery to the populace and future-oriented proficiencies at school to start up levels through organized digital platforms and portals.

MCQs (RAS PRELIMS PATTERN)

1. What is the list of initiatives that have been initiated at the Rajasthan Regional AI Impact Conference-2026 in Jaipur?

(a) Rajasthan AI-ML Policy 2026, National AI Literacy Program, iStart LMS, Rajasthan AVGC-XR Portal, Rajasthan AI Portal.

(b) Rajasthan EV Policy 2026, State Blockchain Mission, Rajasthan Cyber grid, AI University Portal, Skill Rajasthan App.

(c) Rajasthan Drone Policy, National Quantum Program, Digital Health Grid, Startup Funding Portal, Smart City Dashboard.

(d) Rajasthan Space Policy, Digital Police Portal, State Robotics Mission, e-Court System, Rural Broadband Portal.

Answer: (a)

The program at JECC, Jaipur involved the release of the National AI Literacy Program, Rajasthan AI-ML Policy 2026, iStart LMS, Rajasthan AVGC-XR Portal and Rajasthan AI Portal.

2. What was special about the presentation of the signing of the MoU during the event at JECC?

(a) MoUs had been concluded only by means of video conferencing without any presentation.

(b) MoUs were projected live in a holography projection 98 inch screen.

(c) SMARTphones were used to sign MoUs with the use of biometric authentication.

(d) MoUs were publicized by way of printed press notes.

Answer: (b)

The signing of the MoU that took place in Yojana Bhawan was displayed at JECC on a 98-inch holographic projection screen as a live holographic experience.

3. What is the course in the first phase through the National AI Literacy Program?

(a) Yuva AI for All; 4-hour course

RASonly

(b) AI Teacher Mission; 10 days course.

(c) Code Rajasthan; 2-week course

(d) AI Startup Bridge; 30 hour course.

Answer: (a)

The initial stage is Yuva AI for All, which will be provided as a 4-hour course to introduce AI in easy and practical way and make it used responsibly.

राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026 एवं राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेईसीसी, जयपुर में आयोजित "राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस-2026" (06 जनवरी) के उद्घाटन सत्र में राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026 तथा राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर राज्य सरकार ने iStart लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर पोर्टल तथा राजस्थान एआई पोर्टल भी लॉन्च किए। इन पहलों के माध्यम से राजस्थान में एआई आधारित शिक्षा, स्टार्टअप्स, शोध, कौशल विकास और डिजिटल गवर्नेंस को गति देने के साथ-साथ उभरते आईटी क्षेत्रों में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है।

जेईसीसी, जयपुर में घोषित प्रमुख लॉन्च

- राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम
- राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026
- iStart लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS)
- राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर पोर्टल
- राजस्थान एआई पोर्टल

होलोग्राफिक एमओयू साइनिंग का लाइव प्रस्तुतीकरण

- योजना भवन में हुए तीन प्रमुख एमओयू को जेईसीसी में 98-इंच की होलोग्राफिक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर लाइव प्रदर्शित किया गया।
- इसे सरकारी लाइव आयोजन में पहली बार होलोग्राफिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किए जाने के रूप में बताया गया, जबकि इससे पहले यह तकनीक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जी-20 जैसे मंचों पर दिखाई गई थी।
- यह होलोग्राफिक प्रस्तुतीकरण iStart में पंजीकृत स्टार्टअप "कलेन्स" द्वारा विकसित किया गया, जिसके डेवलपर रजत जैन हैं।
- एमओयू में गूगल, आईआईटी दिल्ली तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) जोधपुर शामिल रहे।

RASonly

राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026: एआई आधारित ई-गवर्नेंस पर फोकस

राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026 का उद्देश्य राजस्थान को आईटी/आईटीईएस हब के रूप में विकसित करना तथा सार्वजनिक सेवा वितरण में एआई और मशीन लर्निंग के उपयोग से ई-गवर्नेंस का विस्तार करना है। नीति में एआई/एमएल के उत्तरदायी, नैतिक और सुरक्षित उपयोग पर जोर दिया गया है ताकि सरकारी सेवाएँ अधिक तेज, अधिक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बन सकें। इसके साथ ही प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने तथा नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्य उद्देश्य

• उत्तरदायी एआई/एमएल के उपयोग से नागरिक सेवाओं का वितरण अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना।
• प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना तथा नवाचार-आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना।
• शासन में नैतिक, जवाबदेह और गोपनीयता-संरक्षित एआई प्रणालियाँ सुनिश्चित करना।

डेटा सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा पर प्रावधान

• एआई प्रणालियों में पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और गोपनीयता संरक्षण सुनिश्चित करने पर फोकस।
• एआई सिस्टम में संभावित पक्षपात को कम करने तथा निर्णय प्रक्रिया में स्पष्टता बढ़ाने के प्रावधान।
• एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएँ।
• राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव।

क्रियान्वयन एवं क्षमता निर्माण

• प्रत्येक विभाग अपने क्षेत्र में एआई उपयोग की संभावनाएँ/यूज-केस पहचान करेगा और एक एआई नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।
• आधुनिक डिजिटल और कंप्यूट अवसंरचना, एआई क्लाउड सेवाएँ, सुरक्षित डेटा स्टोरेज तथा टेस्टिंग वातावरण विकसित किए जाएंगे।
• स्कूलों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों और कॉलेजों में एआई शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
• युवाओं, शिक्षकों और सरकारी कार्मिकों के लिए एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
• उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों को आरआईपीएस, एमएसएमई और स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप टॉप-अप प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान।

राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम: “एआई फॉर ऑल” को सरल और व्यावहारिक रूप में

• आमजन को एआई साक्षर बनाने और व्यावहारिक तकनीकी कौशल विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया।
• यह केवल विशेषज्ञों और कोडर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों और सामान्य युवाओं के लिए भी एआई की बुनियादी समझ विकसित करने पर केंद्रित है।
• पहला चरण “युवा एआई फॉर ऑल” है, जिसमें 4 घंटे का कोर्स शामिल है।
• कोर्स में एआई को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया जाएगा तथा क्रिएटिविटी, प्लानिंग और दैनिक जीवन जैसे क्षेत्रों में इसके जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग पर जानकारी दी जाएगी।

RASonly

गूगल, आईआईटी दिल्ली और एनएलयू जोधपुर के साथ एमओयू

• गूगल: स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन और नागरिक सेवाओं में एआई/एमएल आधारित पायलट परियोजनाएँ तथा क्लाउड एवं एआई कार्यान्वयन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का सहयोग।
• एनएलयू जोधपुर: विश्वसनीय, उत्तरदायी और नैतिक एआई को बढ़ावा तथा सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप्स और पेशेवरों का क्षमता निर्माण।
• आईआईटी दिल्ली: एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, शोध, स्किलिंग, हैकाथॉन, स्टार्टअप मेंटरिंग और उद्योग-अकादमिक-सरकारी सहयोग को मजबूत करने हेतु साझेदारी।

निष्कर्ष

राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026 और राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम राजस्थान में एआई आधारित शासन, कौशल विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहलें हैं। नीति के तहत नैतिक सुरक्षा उपायों, साइबर सुरक्षा पर जोर, विभाग स्तर पर एआई अपनाने की व्यवस्था तथा गूगल, आईआईटी दिल्ली और एनएलयू जोधपुर जैसी संस्थाओं के साथ साझेदारियों के माध्यम से राज्य सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने और स्कूल से स्टार्टअप तक भविष्य-तैयार क्षमताएँ विकसित करने का लक्ष्य रखता है।

MCQs (RAS प्रीलिम्स पैटर्न)

1. राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस-2026 में जयपुर में कौन-सी पहलों का समूह लॉन्च किया गया?
(a) राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026, राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम, iStart LMS, राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर पोर्टल, राजस्थान एआई पोर्टल
(b) राजस्थान ईवी पॉलिसी 2026, स्टेट ब्लॉकचेन मिशन, राजस्थान साइबर ग्रिड, एआई यूनिवर्सिटी पोर्टल, स्किल राजस्थान ऐप
(c) राजस्थान ड्रोन पॉलिसी, राष्ट्रीय क्वांटम प्रोग्राम, डिजिटल हेल्थ ग्रिड, स्टार्टअप फंडिंग पोर्टल, स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड
(d) राजस्थान स्पेस पॉलिसी, डिजिटल पुलिस पोर्टल, स्टेट रोबोटिक्स मिशन, ई-कोर्ट सिस्टम, रूरल ब्रॉडबैंड पोर्टल
उत्तर: (a)
जेईसीसी, जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम, राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026, iStart LMS, राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर पोर्टल और राजस्थान एआई पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

2. जेईसीसी में एमओयू साइनिंग के प्रस्तुतीकरण में क्या विशेष था?
(a) एमओयू केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिना किसी प्रदर्शन के किए गए
(b) एमओयू 98-इंच की होलोग्राफिक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर लाइव प्रदर्शित किए गए
(c) स्मार्टफोन पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से एमओयू साइन किए गए
(d) एमओयू केवल मुद्रित प्रेस नोट के माध्यम से सार्वजनिक किए गए
उत्तर: (b)
योजना भवन में हुए एमओयू साइनिंग को जेईसीसी में 98-इंच की होलोग्राफिक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर लाइव होलोग्राफिक अनुभव के रूप में प्रदर्शित किया गया।

RASonly

3. राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम के पहले चरण का कोर्स और उसकी अवधि क्या है?
(a) युवा एआई फॉर ऑल; 4 घंटे का कोर्स
(b) एआई टीचर मिशन; 10 दिन का कोर्स
(c) कोड राजस्थान; 2 सप्ताह का कोर्स
(d) एआई स्टार्टअप ब्रिज; 30 घंटे का कोर्स
उत्तर: (a)
पहला चरण "युवा एआई फॉर ऑल" है, जिसमें 4 घंटे के कोर्स के माध्यम से एआई को सरल और व्यावहारिक रूप में समझाया जाता है तथा इसके जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के बारे में जानकारी दी जाती है।

RASonly

Rajasthan Digifest TiE Global Summit 2026– Voices for the Planet.

In Jaipur, on 6 January, at the third day of the Rajasthan Digifest TiE Global Summit-2026, an event was organized in the main hall called Voices for the Planet: Creativity, Capital and Climate Action. A close dialogue between the chairman of Cyber Media Group Pradeep Gupta and Ricky Kej, a music composer and environmentalists, and IvyCap Founder Vikram Gupta took place. The focus was on transforming environmental action into a more practical approach, music and creativity as a means of developing people engagement, startups to align with the policy of the United Nations on sustainable development goals (SDGs), and assisting in climate solutions by investing in innovation and creative industries.

KEY DISCUSSION HIGHLIGHTS

- The session stressed that environmental issues are to be solved through a common responsibility.
- Orators emphasized that awareness is not sufficient and campaigns should turn into reality and practicality.
- The idea of music was also emphasized as a powerful tool to convey environmental information and get people to do something.
- Startups in the field of environmental solutions were invited to make their activity correspond to the UN SDGs.
- Through the discussion, it was observed that India is experiencing massive undertaking on green and renewable energy with the companies supporting the vision of Atmanirbhar Bharat.

- Climate protection cannot be achieved by the policy alone, but through innovation, art, and creative industries, effective solutions could be developed.
- And, as a means of facilitating sustainable development and preserving environmental balance, there was also the introduction of creativity capital.

WHY This is Important to Governance and Policy.

- The involvement of the people is essential in protecting the environment, and behavioural change can be reinforced with the help of communication tools, such as music.
- A startup innovation in line with SDGs can assist in linking local solutions to globally agreed sustainability priorities.
- Policy action can be complemented by investing in the innovation and the creative spheres to help the availability of scalable climate solutions.

CONCLUSION

The Voices for the Planet session has emphasized the fact that successful climate action requires practical campaigns, robust citizen involvement and innovation-supported solutions. Music and creativity will be able to motivate a behaviour change and prompt community participation. To bridge between local solutions and global priorities, startups are advised to be in line with UN SDGs. Scalable, sustainable ideas as well as policy can be funded by creativity capital.

MCQs (RAS PRELIMS PATTERN)

1. The theme was discussed primarily in the session, Voices for the Planet: Creativity, Capital and Climate Action, at the Rajasthan Digifest TiE Global Summit -2026.

A. e-commerce compliance and digital tax reform.

(b) Invention, investment, and climate action through cultivating the public.

(c) Cyber defence strategy and modernisation of the military.

(d) Heritage branding as a way of promoting tourism.

Answer: (b)

The meeting was dedicated to climate action via practical campaigns, the place of music and creativity, and investment support of sustainable solutions.

2. The discourse in the session indicates that why can music matter as far as environmental protection is concerned?

(a) It substitutes the necessity of environmental laws.

RASonly

(b) It is also capable of conveying messages and encouraging the masses to act.

(c) It lowers the price of renewable energy ventures.

(d) It is predominantly applicable in technical training of coders.

Answer: (b)

The environmental messages can be presented through music in an engaging manner and the music can motivate more people to join the cause of conservation.

3. What was the recommendation on startups whose work involves environmental solutions?

(a) They must not look far, but must concentrate on the local.

(b) They are expected to support the work with the UN Sustainable Development Goals (SDGs).

(c) They ought to cease doing renewable energy and switch to the traditional energy.

(d) They ought to rely on policy change and not innovation.

Answer: (b)

According to the speakers, the startups dealing with the environmental issues needed to operate in the frame of the 17 SDGs, which are created by the UN to integrate environmental protection, social balance, and economic development.

RASonly

राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026— "वॉइसेज फॉर द प्लेनेट"

जयपुर में 6 जनवरी को राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 के तीसरे दिन मुख्य हॉल में "वॉइसेज फॉर द प्लेनेट: क्रिएटिविटी, कैपिटल और क्लाइमेट एक्शन" नामक सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में साइबर मीडिया ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने म्यूजिक कंपोजर एवं एनवायरनमेंटलिस्ट रिक्की केज तथा आइवीकैप के फाउंडर विक्रम गुप्ता के साथ विस्तृत संवाद किया। चर्चा का फोकस पर्यावरणीय कार्रवाई को अधिक व्यावहारिक बनाने, जनभागीदारी विकसित करने में संगीत और रचनात्मकता की भूमिका, पर्यावरण समाधान पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स (SDGs) के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता, तथा नवाचार और रचनात्मक उद्योगों में निवेश के जरिए जलवायु समाधान को समर्थन देने पर रहा।

मुख्य चर्चा बिंदु

• सत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से होना चाहिए।
• वक्ताओं ने कहा कि केवल जागरूकता पर्याप्त नहीं है, अभियानों को ठोस और व्यावहारिक रूप में बदलना जरूरी है।
• संगीत को पर्यावरण संदेश पहुंचाने और लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने वाला प्रभावी माध्यम बताया गया।
• पर्यावरणीय समाधान पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को संयुक्त राष्ट्र के SDGs के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।
• चर्चा में यह भी कहा गया कि भारत में ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम हो रहा है और कंपनियां आत्मनिर्भर भारत की दिशा में योगदान दे रही हैं।
• यह दृष्टिकोण सामने आया कि जलवायु संरक्षण केवल नीतिगत प्रयासों से नहीं हो सकता; नवाचार, कला और रचनात्मक उद्योगों के जरिए प्रभावी समाधान विकसित किए जा सकते हैं।
• सतत विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने वाले विचारों को समर्थन देने के लिए "क्रिएटिविटी कैपिटल" की अवधारणा भी सामने रखी गई।

शासन एवं नीति के लिए महत्व

• पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है और संगीत जैसे संचार माध्यम व्यवहार परिवर्तन को मजबूत कर सकते हैं।
• SDGs के अनुरूप स्टार्टअप नवाचार स्थानीय समाधानों को वैश्विक रूप से स्वीकृत सततता प्राथमिकताओं से जोड़ने में मदद कर सकता है।
• नवाचार और रचनात्मक क्षेत्रों में निवेश नीति-आधारित प्रयासों को पूरक बनाकर ऐसे जलवायु समाधानों को आगे बढ़ा सकता है, जिन्हें बड़े स्तर पर लागू किया जा सके।

निष्कर्ष

"वॉइसेज फॉर द प्लेनेट" सत्र ने रेखांकित किया कि सफल जलवायु कार्रवाई के लिए व्यावहारिक अभियान, मजबूत नागरिक सहभागिता और नवाचार-समर्थित समाधान आवश्यक हैं। संगीत और रचनात्मकता व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित कर समुदाय की भागीदारी बढ़ा सकती है। स्थानीय समाधानों को वैश्विक प्राथमिकताओं से जोड़ने के लिए स्टार्टअप्स को संयुक्त राष्ट्र के SDGs के अनुरूप कार्य करने की सलाह दी गई। "क्रिएटिविटी कैपिटल" के माध्यम से नीति के साथ-साथ स्केलेबल और सतत विचारों को वित्तपोषित किया जा सकता है।

RASonly

MCQs (RAS प्रीलिम्स पैटर्न)

1. राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 में "वॉइसेज फॉर द प्लेनेट: क्रिएटिविटी, कैपिटल और क्लाइमेट एक्शन" सत्र में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा हुई?
   (a) ई-कॉमर्स अनुपालन और डिजिटल कर सुधार
   (b) जनभागीदारी के माध्यम से नवाचार, निवेश और जलवायु कार्रवाई
   (c) साइबर रक्षा रणनीति और सैन्य आधुनिकीकरण

(d) पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हेरिटेज ब्रांडिंग
उत्तर: (b)
इस सत्र में व्यावहारिक अभियानों के माध्यम से जलवायु कार्रवाई, संगीत और रचनात्मकता की भूमिका तथा सतत समाधानों के लिए निवेश समर्थन पर चर्चा केंद्रित रही।

2. सत्र में हुई चर्चा के अनुसार पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में संगीत क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है?
(a) यह पर्यावरण कानूनों की आवश्यकता को समाप्त कर देता है
(b) यह संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाकर जनसामान्य को कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकता है
(c) यह रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं की लागत कम कर देता है
(d) यह मुख्यतः कोडर्स के तकनीकी प्रशिक्षण में उपयोगी है
उत्तर: (b)
संगीत के माध्यम से पर्यावरणीय संदेश आकर्षक और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिससे अधिक लोगों को संरक्षण के लिए प्रेरणा मिलती है और व्यापक जनभागीदारी संभव होती है।

3. पर्यावरण समाधान पर काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए क्या सिफारिश की गई?
(a) उन्हें केवल स्थानीय उद्देश्यों पर ध्यान देना चाहिए और वैश्विक ढांचों से बचना चाहिए
(b) उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स (SDGs) के अनुरूप कार्य करना चाहिए
(c) उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी छोड़कर पारंपरिक ऊर्जा पर जाना चाहिए
(d) उन्हें नवाचार के बजाय केवल नीतिगत बदलावों पर निर्भर रहना चाहिए
उत्तर: (b)
वक्ताओं के अनुसार पर्यावरणीय समस्याओं पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 SDGs के ढांचे में कार्य करना चाहिए, जिनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक संतुलन और आर्थिक विकास को एक साथ आगे बढ़ाना है।

RASonly

RASonly